

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मु.मंत्री चंद्रबाबू नायडू को लताड़ लगाई

‘आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बिना वैरिफाई किए कोई खबर जारी करना जिम्मेवारी का काम नहीं है’

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 सितम्बर। राजनैतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के उपयोग पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुये, सर्वोच्च न्यायालय ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाते हुये कहा कि उन्होंने सुप्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति मंदिर में “प्रसादम” के रूप में लड्डू तैयार करने के लिये मिलावटी घी के उपयोग के बारे में सार्वजनिक बयान दे दिया। अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा आदेशित जाँच के नतीजे की प्रतीक्षा किये बिना ही उनके द्वारा इस प्रकार का बयान देना सर्वथा अनुचित था।

न्यायमूर्ति जी.आर. गवई तथा के.जी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा, “हम यह अपेक्षा रखते हैं कि भगवान राजनीति से दूर रखे जायें।” बेंच ने यह जानना चाहा कि जब इस मामले की जाँच के आदेश दिये जा चुके हैं तथा रिपोर्ट प्रतीक्षित है तो ऐसी स्थिति में क्या सार्वजनिक बयान देना जरूरी था।

बेंच ने कहा, “प्रथम दृष्टया, हमारा मानना है कि जब जाँच-पड़ताल

- सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी. गवई और जस्टिस के.जी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा, तिरुपति मंदिर के प्रसादम में पशु चर्बी मिलाई जा रही है, इस बात की सरकार द्वारा शुरु कराई गई जाँच की रिपोर्ट आने तक मुख्यमंत्री नायडू को इंतज़ार करना चाहिए।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकारी जाँच रिपोर्ट आए बिना ही ऐसी घोषणा करना मामले का राजनीतिकरण करने जैसा है। बेंच ने कहा, “कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखिए।”

- सुप्रीम कोर्ट में प्रसादम में पशु चर्बी की मिलावट की स्वतंत्र जाँच की माँग करते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा सांसद और तिरुपति तिरुमला देवस्थान के पूर्व चेयरमैन वाय. सुब्बारेड्डी, इतिहासकार सम्पत, आध्यात्मिक गुरु दुष्यंत श्रीधर व पत्रकार सुरेश चट्टण शामिल हैं। मामले पर अब 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

प्रक्रियाधीन है, इतनी उच्च संवैधानिक सत्ता (नायडू) के लिये ऐसा बयान देना उचित नहीं था, जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सके।” बेंच ने यह तय करने के लिए सॉलिडिटर

जनरल तुषार मेहता की सहायता चाही कि क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एस.आई.टी. जारी रहने देनी चाहिए या जाँच का काम किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाना चाहिये।

अदालत ने मेहता से कहा कि वे इस मुद्दे पर केन्द्र से निर्देश ले लें। इसके बाद, इस प्रकरण की अगली सुनवाई के लिये 3 अक्टूबर की तिथि मुकर्र कर दी।

तिरुपति मंदिर में प्रसादम तैयार करने के लिये जानवरों की चर्बी के कथित प्रयोग की स्वतंत्र जाँच कराने की माँग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुये, उच्चतम न्यायालय ने यह जानना चाहा कि क्या यह कहने का कोई प्रमाण है कि लड्डू बनाने में दूधित घी काम में लिया गया।

याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं— भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, वार्ड.जी. सुबा रेड्डी, जो राज्यसभा सांसद हैं और तिरुपति मंदिर का प्रबंधन करने वाले “तिरुपति तिरुमला देवस्थान” के पूर्व चेयरमैन हैं। इतिहासकार विक्रम सम्पत, आध्यात्मिक गुरु दुष्यंत श्रीधर तथा सुदर्शन न्यूज एडिटर—इन-चीफ सुरेश चट्टण।

मेहता ने कहा कि यह आस्था का मामला है तथा अगर तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने में दूधित घी का उपयोग हुआ था, तो यह अस्वीकार्य है।

(श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

कोलकाता की एतिहासिक विरासत “ट्राम” बंद होंगी

-जाल खंभाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 सितम्बर। ममता बनर्जी ने ट्राम-सेवाएँ बंद करने का निर्णय लिया है। ज्ञातव्य है कि कोलकाता में पहली ट्राम 24 फरवरी, 1873 को चली थी। अभी हाल ही, 2013 में कोलकाता में ए.सी. ट्राम चलना शुरु हो गई है। लेकिन यह अभी तय नहीं है कि क्या सभी ट्राम एक साथ ही बंद कर दी जायेंगी। इसके अलावा,

- पश्चिम बंगाल सरकार ने अंततः “ट्राम” सर्विस बंद करने का निर्णय ले लिया है। कोलकाता में 24 फरवरी 1873 को ट्राम सेवा शुरु हुई थी।

इन्हें बंद करने की तिथि भी घोषित नहीं की गई है।

कोलकाता ऐसा एकमात्र शहर है, जहां ट्राम अभी भी चलती हैं। मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, पटना तथा नासिक जैसे उपनिवेशीय नगरों में ये पहले ही बन्द हो चुकी हैं। कोलकाता अब तक अपनी इस “विरासत एवं सांस्कृतिक प्रतीक” को सहेजे हुये था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन्हें बन्द करने का निर्णय आखिर ले ही लिया।

(श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी की हरियाणा के लिए सौगातें

-जाल खंभाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 सितम्बर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ही प्रतिमाह 2,000 रूपए डाले जाएंगे तथा गैस सिलेंडर 700 रूपए की बजाय 500 रूपए में मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। विधवाओं, बूढ़ों व दिव्यांगों के लिए प्रति माह 6,000 रूपए दिये जाएंगे।

राहुल हरियाणा के अम्बाला जिले की नरसिंहगढ़ सीट पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहाँ 5 अक्टूबर को चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि जो पैसा केन्द्र सरकार ने अडानी-अम्बानी को दिया, उसे सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों व दलितों के सम्मान में खर्च करेगी।

राहुल ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और कर्ज में राहत देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि यह सब बहुत आसान है क्योंकि कांग्रेस पैसा गरीबों को देगी, यह पैसा उन्हीं की जेब से छीना गया है। केन्द्र सरकार अडानी का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ करती है, हमारी योजना हरेक गरीब महिला के खाते में एक लाख रूपए ट्रांसफर करने की है। क्यों न किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। उन्होंने 2 लाख राज्य

- राहुल गांधी ने महिलाओं के बैंक खाते में प्रति माह 2,000 रूपए हस्तान्तरित करने, गैस सिलेंडर 500 रूपए में के देने की घोषणा की।

- राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना वापस लायी जाएगी, साथ ही विधवाओं बुजुर्गों व दिव्यांगों को प्रति माह 6,000 रूपए दिए जाएंगे।

- राहुल ने कहा, केन्द्र सरकार अडानी का 16 लाख रूपए का कर्ज माफ करती है, हम चाहते हैं किसानों का कर्जा माफ हो। हम उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं।

कर्मचरियों से लेकर हरियाणा के युवा को उसके हक का सम्मान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि गरीबों को 100 गज के भूखंड दिए जाएंगे तथा घर बनाने के लिए साढ़े तीन लाख रूपए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा, 300 युनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीबों के बैंक खातों में रूपए ट्रांसफर करने की बात कही।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हरियाणा में भाजपा दस साल से सत्ता में है। उसने जनता को कोई सम्मान नहीं दिया, बल्कि देश की रक्षा कर रहे सैनिकों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान देश के अन्नदाता हैं।

किसानों ने अपनी एकता से सरकार को तीनों काले कृषि कानून वापस लेने को मजबूर किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का युवा दिल्ली, मुम्बई व अन्य शहरों में जाता है काम के लिए, पर उसे अपने राज्य में सम्मान नहीं मिलता। जिन्हें अग्निवीर में शामिल होने का कहा गया है, उन्हें चार साल बाद बेरोजगारी से लड़ने को छोड़ दिया जाता है।

हरियाणा के युवा में आत्म सम्मान नहीं है। पहलवानों को सड़कों पर उतरना पड़ा। हरियाणा के युवा को आत्म सम्मान के लिए लड़ना पड़ा। वहीं राज्य की भाजपा सरकार सिर्फ घोटालों में उलझी रही।

दुनिया भर में बढ़ रही है भारत की वंदे भारत ट्रेन की मांग

कम लागत और अत्याधुनिक विशेषताओं के प्रति खास आकर्षण है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 सितम्बर। कई देशों, जिनमें चिली, कैनाडा, मिडिल ईस्टर्न देश, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, यहाँ तक कि कुछ विकसित यूरोपियन देश भी शामिल हैं, ने अपने रेल सिस्टम का आधुनिकीकरण करने और परिवहन सेवा का विस्तार करने के लिए वंदे भारत को खरीदने में रुचि दिखाई है।

वंदे भारत ट्रेन का आधुनिक डिजाइन, अत्याधुनिक तकनीक और कम लागत तथा क्षेत्र की जरूरत के आधार पर बदलाव करने की विशेषता इन देशों को आकर्षित कर रही है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है, कम लागत। ऐसी विशेषताओं वाली ट्रेन किसी अन्य देश में बनती है, तो उस पर 160-180 करोड़ रूपए की लागत आती है, पर भारत में एक ट्रेन के निर्माण पर 120 से 130 करोड़ रूपए की लागत आती है।

- वंदे भारत में वाई फ्राई, जी.पी.एस. स्वचालित दरवाजे और आरामदायक सीटें हैं। ऐसी ट्रेन बनाने में विदेश में 160 से 180 करोड़ रु. लगते हैं, पर वंदे भारत ट्रेन के निर्माण में 120 से 130 करोड़ रु. की ही लागत आती है।

- यही वजह है कि चिली, इण्डोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, अरब देश, दक्षिण अफ्रीका व कैनाडा ये ट्रेन खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। यही नहीं, विकसित यूरोपियन देश भी ये ट्रेन खरीदना चाहते हैं।

- वंदे भारत ट्रेन मात्र 52 सैकण्ड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है और इसने जापान की बुलेट ट्रेन को भी मात दे दी है, जिसे ऐसा करने में 54 सैकण्ड लगते हैं। इसके अलावा यह हवाई जहाज की तुलना में 100 गुना कम शोर करती है और ऊर्जा की खपत भी कम होती है।

रफ्तार पकड़ने के मामले में भी वंदे भारत प्रतिद्वंदियों को मात दे सकती है। शून्य से 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ने में वंदे भारत को मात्र 52 सैकण्ड लगते हैं। यहाँ तक कि जापान

की बुलेट ट्रेन को भी इसमें 54 सैकण्ड लगते हैं।
हवाई जहाज की तुलना में वंदे भारत ट्रेन में 100 गुना कम शोर होता (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड

-जाल खंभाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 सितम्बर। प्रख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिये “दादा साहेब फालके” अवॉर्ड दिये जाने की घोषणा सोमवार को कर दी गई। उन्हें यह अवॉर्ड विज्ञान भवन में अक्टूबर में आयोजित होने वाले इंडियन नैशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह में दिया जायेगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी

- प्रधानमंत्री मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

वैष्णव ने सलैक्शन जूरी द्वारा घोषित अवॉर्ड की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा: “मुझे बड़ी खुशी है कि मिथुन चक्रवर्ती जी को प्रतिष्ठित दादा साहेब फालके अवॉर्ड देने की घोषणा की गई है। यह अवॉर्ड उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिये दिया जा रहा है। वे उनके विविधभारतीय प्रदर्शन के लिये सभी पीढ़ियों के प्रशंसित सांस्कृतिक नायक हैं। उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं।”

‘जूनियर डॉक्टर्स से किए गए वादों पर काम क्यों नहीं हो रहा?’

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 सितम्बर। कोलकाता के आर.जी. कार मैडिकल कॉलेज में हुई युवा लेडी डॉक्टर की नृशंस हत्या के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों द्वारा उठाए गए मुद्दों को त्वरित गति से संबोधित करने में असफल रहने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से पूछा कि जूनियर डॉक्टरों से जो वादे किए गए थे, जो काम इतनी धीमी गति से क्यों चल रहे हैं। जितने भी काम करवाने के वादे किए गए थे, उनमें पचास प्रतिशत प्रगति भी नहीं हुई है। इनमें सी.सी.टी.बी. कैमरे लगवाना तथा जूनियर डॉक्टरों के लिए सुविधाओं का निर्माण करवाना शामिल है।
चितना काम हुआ है, उसका रिव्यू करने के बाद, चीफ जस्टिस ने कहा कि जो काम करवाने का वादा किया गया था, उनमें बहुत धीमी प्रगति रही है।
जूनियर डॉक्टर, जो मूलतः

- चीफ जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड़ ने कहा, सी.सी.टी.बी. कैमरा लगाने, टॉयलेट व रैस्ट रूम जैसी सुविधाओं के निर्माण में सरकार बहुत धीमी गति से काम कर रही है।
- इतने बड़े हादसे के बाद भी राज्य सरकार डॉक्टर्स की सुरक्षा के प्रति लापरवाह बनी हुई है। हाल ही में एक सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत पर डॉक्टरों और नर्सों के साथ मरीज के परिजनों ने मारपीट की।

मैडिकल ट्रेनी हैं, ने हत्या के केस में आरोपी को शिनाख्त तथा माफूल मुकदमा चलाने की मांग की है। उन्होंने बीमारों की देखभाल के समय जूनियर डॉक्टरों के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की मांग भी की है।

जूनियर डॉक्टरों ने शिकायत की थी कि उनको न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं मिली हुई हैं, जैसे कि लंबी ड्यूटी के बाद आराम करने की जगह, समुचित सुरक्षा व्यवस्था तथा सुचारु ढंग से काम करने के लिए आवश्यक इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण स्थानों पर सी.सी.टी.बी. कैमरे इन्स्टॉल करने, जूनियर डॉक्टरों के लिए सुविधाओं और विशिष्ट टॉयलेट सुविधाओं जैसे कार्यों की प्रगति को मॉनिटर किया।

तथापि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई मॉनिटरिंग में सामने आया कि राज्य सरकार को सुपुर्द किए गए अधिकतर कार्य हुए नहीं हैं। सी.सी.टी.बी. कैमरे नहीं लगे हैं और ना टॉयलेट सुविधाओं का निर्माण किया गया है।
दोनों तरफ से दिए गए “बर्क कम्प्लीशन डेटा” तथा दस्तावेजों की जांच करने के बाद, कोर्ट ने महसूस

किया कि इन कार्यों में नाम मात्र की प्रगति भी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, हिंसा से नई घटनाएं सामने आई हैं। राज्य सरकार के अस्पताल, सागर दत्ता मैडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल में एक मरीज की मृत्यु के बाद, वहाँ के डॉक्टरों और नर्सों को जनता के प्यों और धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा।

मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टरों के साथ मार पिटाई की है। इस घटनाक्रम ने स्थिति को और जटिल कर दिया है तथा इससे सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था का अभाव सामने आया है।

वायु सेना के नये प्रमुख ने कार्यभार संभाला

नयी दिल्ली, 30 सितम्बर। एयर चीफ मार्शल जी.आर. चौधरी के सोमवार को सेवानिवृत्त होने पर एयर चीफ मार्शल ए.पी.सिंह ने वायु सेना के नये प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया।

वायु सेना के अनुसार, एयर चीफ मार्शल चौधरी ने वायु सेना प्रमुख के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर वायु सेना मुख्यालय में एयर चीफ मार्शल सिंह को वायु सेना की कमान सौंपी।

एयर चीफ मार्शल चौधरी ने सुबह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्हें

- एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह को विभिन्न प्रकार के विमानों पर 5000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है।

वायु सेना मुख्यालय वायु सेना भवन में गाई ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने नये वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल सिंह को कार्यभार सौंपा। एयर चीफ मार्शल सिंह फरवरी 2023 से वायु सेना उप प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस मौके पर वायु सेना के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
एयर चीफ मार्शल सिंह को 21 सितम्बर को नया वायु सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। उन्हें दिसंबर 1984 में भारतीय वायु सेना की फाइटर (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र सरकार ने गाय को “राज्य माता” घोषित किया

मुंबई, 30 सितंबर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को भारत में गायों के सांस्कृतिक महत्व और उसकी परंपराओं का हवाला देते हुए गाय को “राज्य माता” घोषित करने का आदेश जारी किया।

- महाराष्ट्र मंत्रिमण्डल ने देशी गायों के पालन-पोषण के लिये 50 रूपये प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का भी निर्णय लिया है।

आधिकारिक आदेश में महायुति सरकार ने कहा कि गाय भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और प्राचीन काल से ही इसका आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सैन्य महत्व रहा है। आधिकारिक अधिसूचना में शिंदे (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

आदमखोर पैंथर ने पुजारी को सातवां शिकार बनाया

उदयपुर शहर से सटे बड़गांव उपखंड में पैंथर पहुँचने से दहशत फैली

उदयपुर, 30 सितम्बर (निसं)। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के गांवों में आतंक फैला रहा आदमखोर पैंथर गोगुंदा से बड़गांव पहुंच गया है, जहां सोमवार तड़के उसने सातवां इंसानी शिकार किया। आदमखोर पैंथर उदयपुर शहर से सटे बड़गांव उपखंड क्षेत्र की मदार पंचायत के राठौड़ों का गुद्धा गांव में मंदिर के पुजारी, विष्णु गिरी को मारकर खा गया। मंदिर से 400 मीटर दूर मकके के खेत में पुजारी का शव-विक्षत शव मिला है। सूचना मिलने पर कलेक्टर अरविंद पोसवाल सहित पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए गांव के स्कूल को छुट्टी कर दी गयी है और ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है।
कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने

बताया कि पैंथर आदमखोर हो चुका है और अब वह बार-बार इंसानों पर ही हमले करेगा। आदमखोर पैंथर के पैटर्न को देखते हुए विशेषज्ञ बता रहे हैं कि एक शिकार के बाद अगला शिकार वह 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में कर रहा है। पुलिसकर्मी, वनकर्मी और आर्मी के जवान और ग्रामीणों की 20 अलग-अलग टीमों बनायी गयी है, ये सभी टीमों वनक्षेत्र और आस-पास के संभावित स्थानों पर आदमखोर पैंथर की तलाश कर रही है। पुलिस डॉग स्क्वॉड तथा आर्मी के अत्याधुनिक उपकरणों का भी उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों को लाउंड स्पीकर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि आने वाले दो-तीन दिन घर के बाहर न सोएँ, रात को घर से बाहर न निकलें और जब भी

- विशेषज्ञों के अनुसार, पैंथर एक शिकार के बाद 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में दूसरा शिकार कर रहा है। पुलिस, वन विभाग, सेना व ग्रामीणों की 20 टीमों पैंथर की तलाश में लगी हैं।

घर से बाहर निकलें तो समूह बनाकर ही जाएँ।

राठौड़ों का गुद्धा के ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात, गवरी कार्यक्रम के चलते रात तीन बजे तक गांव में चहल-पहल थी। रात तीन बजे तक ग्रामीणों ने सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व पुलिस को सूचना दी। उदयपुर में पैंथर ने 11 दिनों में 7 लोगों का शिकार कर लिया है।
घटना के शिकार हुई महिला उदयपुर डी.एफ.ओ. अजय चितौड़ा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पैंथर को

पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया।
पिछले दिनों हुए कुछ हमलों के बाद वन विभाग अब तक चार पैंथर पकड़ चुका है, फिर भी हमले नहीं रुक रहे हैं। लेकिन, अब तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये हमले एक ही पैंथर ने किये या अलग-अलग पैंथर हैं। लगातार हो रहे इन हमलों ने वन विभाग और प्रशासन को चिंता में डाल दिया है।
पैंथर के हमले उदयपुर के गोगुंदा और झाडोल में हुए हैं। हमले में पैंथर किसी का हाथ उखाड़ कर ले गया तो किसी का सिर घड़ से अलग कर दिया। 28 सितंबर को रात हुए हमले में मौत का शिकार हुई महिला उदयपुर बाई का एक हाथ आज तक नहीं मिला। सिर पर इतने पंजे मारे कि

गिनना भी मुश्किल था। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने रविवार को वन विभाग और पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग की।
बैठक में तय किया गया कि उदयपुर में इको सिस्टम ठीक करने के लिए हिरण, सांभर और खरगोश जैसे जानवरों को गोगुंदा और झाडोल के इलाकों में छोड़ा जाएगा। एक बैन चलाई जायगी जो गांव-गांव जाकर लोगों से अपील करेगी कि अकेले वन्य क्षेत्र में न तो मवेशी चराने और न चारा लेने के लिए ही जाएं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों से बातचीत में सामने आया है कि इलाके का इको सिस्टम दुरुस्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी कई गैप सामने आए हैं। इन्हें आगामी दिनों में ठीक करने का प्रयास किया जायेगा।